प्रतिदिन

भयावह त्रासदी

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के लिए भी यह आसान नहीं रहा होगा. इराक में काम करने गए 39 भारतीय कर्मचारियों के मारे जाने की खबर उन्होंने कितने भरे मन से दी होगी, इसे समझा जा सकता है. खासकर तब, जब पिछले तकरीबन चार साल से वह इन लोगों के परिजनों और साथ में पूरे देश को सरकार की तरफ से यह आश्वासन दे रही थीं कि इन लोगों को बचा लिया जाएगा. हालांकि जैसे-जैसे समय निकलता जा रहा था, ये आश्वासन भी अपना अर्थ खोते जा रहे थे. ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इसके लिए कोशिश नहीं की होगी. लेकिन इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने जिस क्षेत्र में यह वारदात की, वहां भारत सरकार तो दूर, उस समय इराक सरकार तक की पहुंच भी नहीं थी. वह ऐसा क्षेत्र था, जहां न भारत की कूटनीति कुछ काम कर सकती थी और न ही भारत की सैन्य ताकत. यहां तक कि उस इलाके में भारत की खुफिया उपस्थिति भी नहीं थी. हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी थी.

इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले मोसुल इलाके से उसी वक्त के दौरान भारत ने जिस तरह केरल की नर्सों को मुक्त कराया और उन्हें भारत वापस लाने में सफलता हासिल की गई, वह बताता है कि सरकार इस मसले पर लगातार सक्रिय थी. लेकिन इन 39 लोगों के मामले में यह सक्रियता भी किसी काम नहीं आ सकी. आतंकवादी संगठन ने निर्माण मजदूरों के तौर पर वहां काम करने गए इन लोगों की न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि उनके शवों को एक सामूहिक कब्रा में दफ्न कर दिया. यह मामला सिर्फ सरकार के प्रयासों का और उनके अंजाम तक न पहुंच पाने का ही नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और हमारे नौजवानों के बारे में भी काफी कुछ कहता है. खबरों में बताया गया है कि ये सारे नौजवान महज 35 हजार रुपये महीने की नौकरी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गए, और एक ऐसे इलाके में पहुंच गए, जिसे आज भी मौत की घाटी माना जाता है. यह बताता है कि हमारे नौजवानों पर जीवनयापन के दबाव कितने बड़े हैं और उनके विकल्प कितने सीमित हैं. ऐसे विकल्प कोई जान-बूझकर नहीं, बल्कि मजबूरी में ही चुनता है. यही बात इन 39 लोगों के बारे में भी कही जा सकती है और केरल की उन लड़कियों के बारे में भी, जो नर्स की नौकरी करने के लिए युद्धग्रस्त क्षेत्र जाने को तैयार हो गई थीं.

सरकार अपनी तरफ से लगातार ऐसी चेतावनी जारी करती रहती है कि भारतीयों को कामकाज या नौकरी के सिलसिले में किन क्षेत्रों में जाना चाहिए और किन क्षेत्रों में नहीं. यह काम भी अपने आप में जरूरी है, लेकिन अब लगता है कि सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है. सरकार को उन एजेंटों और दलालों पर भी लगाम कसनी होगी, जो युद्धग्रस्त और अशांत क्षेत्रों के लिए नौजवानों की भर्ती करते हैं. यह भी मुमकिन है कि बहुत से मामलों में इन नौजवानों को यह ठीक से बताया ही न जाता हो कि उन्हें किस क्षेत्र में या कैसी जगह पर तैनात किया जाएगा. हालांकि सबसे बेहतर तो यही है कि नौजवानों के लिए देश में ही रोजगार के सम्मानजनक और पर्याप्त अवसर पैदा किए जाएं. जब तक यह नहीं हो सकता, उन्हें किसी भी तरह के खतरे से बचाना समाज और सरकार, दोनों की जिम्मेदारी है. अब जब देश के 39 बहादुर नौजवानों की मौत की खबर हमें मिली है, तो यह संकल्प हमें लेना ही होगा.

गहरा पैठा आतंकवाद

आतंकियों के पैसे पर कैसे लगे लगाम ?

तमाम प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों को कमजोर करने के मोर्चे पर भारत सहित पश्चिमी देशों को खास सफलता नहीं मिली है. भारत के लिए इससे ज्यादा निराशाजनक बात क्या हो सकती है कि इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद की पार्टी मिल्ली मुसलिम लीग के पंजीकरण का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद हाफिज की पार्टी इस साल होने वाले नेशनल असेंबली के चुनाव लड़ सकेगी.

इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने पाकिस्तानी चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें हाफिज की पार्टी का पंजीकरण संबंधी आवेदन रद्द कर दिया गया था. हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग को हाफिज की पार्टी के पंजीकरण का आदेश दिया है. यही नहीं, हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार के आतंकवाद निरोधी अध्यादेश-2018 को भी इस्लामाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी है. पाकिस्तान के अंदर तमाम आतंकी संगठनों की गतिविधियां पहले की तरह तेज हैं. मतलब साफ है. अमेरिका और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के दबाव के बावजूद पाकिस्तान सरकार और सेना आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं. भारत की चिंता यही है. हाफिज सईद की खुली गतिविधियों पर भारत ने जो गंभीर चिंता व्यक्त की है, उस चिंता का शायद ही कोई असर पाकिस्तान पर दिख रहा है.

कुछ समय पहले ही अंतरराष्ट्रीय संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) ने पाकिस्तान को आतंकी पूंजी निगरानी सूची में डालने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान सरकार अपने यहां सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में पाकिस्तान को जून में निगरानी सूची में डाल दिया जाएगा. कार्य बल के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव पड़ेगा. इस मजबूरी में पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करेगा.

तर्क दिया जा रहा है कि निगरानी सूची में आने के बाद पाकिस्तान का अंतराष्ट्रीय व्यापार घटेगा और विदेशी निवेश पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा. लेकिन फिलहाल पाकिस्तान पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है. हालांकि पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि निगरानी सूची में आने के बाद भी उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जब 2012 से 2015 तक पाकिस्तान को इस सूची में डाला गया था, उस दौरान भी उसने अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ कई समझौते किए थे. इस समय पाकिस्तान में सबसे बड़ा निवेश चीन का है. पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाले जाने की सूरत में चीन उसके प्रति कितना सख्त होगा, यह समय बताएगा.

पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के पास पूंजी जुटाने के कई स्रोत हैं. अफगानिस्तान में सक्रिय अफगान-तालिबान, भारत विरोधी लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान विरोधी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान कई तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं. पैसा जुटाने के लिए आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा जरिया अपहरण और वसूली है. इसके अलावा आतंकी संगठनों ने आधुनिक व्यवसायों में भी निवेश कर रखा है. कई कंपनियां बना कर आतंकी संगठनों ने परिवहन, अचल संपत्ति और निर्माण के कारोबार में निवेश कर रखा है. पाकिस्तानी सुरक्षा एजंसियां और सरकार इसे रोक पाने में नाकाम रही हैं.

इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय एजंसियां भी आतंकी संगठनों के कारोबार की तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं. यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी के कॉम्बेटिंग टेररिज्म सेंटर ने हक्कानी नेटवर्क के वित्तीय कारोबार पर विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट में हक्कानी नेटवर्क के तमाम कारोबार और पूंजी संग्रह के तरीकों की जानकारी दी गई है.

हक्कानी नेटवर्क ने पाकिस्तान और उसके बाहर अचल संपति और निर्माण क्षेत्र में खासा निवेश किया हुआ है. अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान के पाकिस्तान के सिंध और खैबर पख्तूनवा में परिवहन क्षेत्र में कारोबार है. ट्रांसपोर्ट यूनियनों पर तालिबान समर्थित गुटों का कब्जा है. कराची, लाहौर सहित कुछ बड़े शहरों के अचल संपति कारोबार में तालिबान का पैसा लगा है. पाकिस्तान से बाहर दुबई, अबूधाबी, दोहा जैसे अरब शहरों में हक्कानी नेटवर्क ने अचल संपति कारोबार में खासा पैसा लगा रखा है. इसकी विस्तृत जानकारी अमेरिकी, जर्मन, ब्रिटिश खुफिया एजंसियों को है. यही नहीं, नाटो सप्लाई लाइन को सुचारु रूप से चलने देने के लिए भी अमेरिका से तालिबान वसूली करता है.

आतंकी संगठनों की इस तरह से धन उगाही के लिए अकेले पाकिस्तान जिम्मेवार नहीं है. वैसे भी पाकिस्तानी सुरक्षा एजंसियों से आतंकियों पर कार्रवाई की उम्मीद करना फिजूल है. पर पश्चिमी मुल्कों की एजंसियां भी इस मामले में कार्रवाई करने में विफल रही हैं. आतंकियों को मिलते धन को लेकर कई पश्चिमी देशों और आतंकी संगठनों के बीच लुका-छिपी का खेल चलता है. वर्ष, 2008 से 2014 के बीच फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई यूरोपीए देशों और आतंकी संगठनों के बीच पैसे के लेन-देन की कलई खुल चुकी है.

आतंकी संगठनों की एक और मुख्य पूंजी अफीम की खेती है. पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी पूंजी का एक बड़ा स्रोत अफगानिस्तान में अफीम की खेती है. लेकिन नाटो सेना ने अफीम की खेती को खत्म करने के प्रयास नहीं किए. अफीम की खेती से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा तालिबान कमांडरों को जाता है. पिछले सत्रह सालों से नाटो सेना की मौजूदगी के बावजूद अफगानिस्तान में अफीम की खेती में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है. तालिबान के ज्यादातर कमांडर पाकिस्तानी क्षेत्र से अफीम का कारोबार करते हैं. अफीम की खेती को लेकर नाटो सेना, अफगानिस्तानी हुक्मरान और तालिबान के बीच एक तरह से मौन सहमति है. अफीम कारोबार से होने वाली आमद का खासा हिस्सा अफगान सरकार के ताकतवर लोगों को जाता है.

अफीम की खेती से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा तालिबान कमांडरों को जाता है. पिछले सत्रह सालों से नाटो सेना की मौजूदगी के बावजूद अफगानिस्तान में अफीम की खेती में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है. तालिबान के ज्यादातर कमांडर पाकिस्तानी क्षेत्र से अफीम का कारोबार करते हैं. अफीम की खेती को लेकर नाटो सेना, अफगानिस्तानी हुक्मरान और तालिबान के बीच एक तरह से मौन सहमति है. अफीम कारोबार से होने वाली आमद का खासा हिस्सा अफगान सरकार के ताकतवर लोगों को जाता है.

दरअसल, आतंकियों को होने वाली फंडिंग को खत्म करने के नाम पर ढोंग रचा गया है. इसलिए आतंकी पूंजी को रोकने के लिए जरूरी है कि दुनिया के कई मुल्कों में फैले आतंकी संगठनों के कारोबार को ध्वस्त किया जाए. साथ ही, अफगानिस्तान में अफीम की खेती को पूरी तरह नष्ट करना होगा. लेकिन हालात इसके उलट हैं. अफगानिस्तान में अफीम की खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है. वर्ष,1994 में अफगानिस्तान में मात्र तीस हजार हेक्टेयर में अफीम की खेती होती थी. लेकिन दो दशक के भीतर ही इसमें भारी इजाफा होता चला गया. वर्ष, 2016 में अफीम की खेती का रकबा बढ़ कर दो लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया. और 2017 में यानी एक साल में ही तीन लाख तीस हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया. पिछले साल नब्बे लाख किलो अफीम की खेती हुई. इस समय दुनिया के कुल अफीम उत्पादन का सत्तर फीसद हिस्सा अफगानिस्तान में हो रहा है. अफीम संग्रहण के लिए तालिबान ने अफगानिस्तान में लगभग ढाई हजार गोदाम बना रखे हैं.इन परिस्थितियों में पाकिस्तान को सिर्फ निगरानी सूची में डाले जाने से कोई हल नहीं निकलेगा. अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को कई मोर्चों पर एक साथ कदम उठाने होंगे. अफगानिस्तान में अफीम की खेती को खत्म करने के लिए अफगान किसानों को गेहूं और अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना होगा.

इसके लिए किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य देना होगा. लेकिन इस दिशा में अफगान सरकार की ओर से कोई कोशिश नहीं हुई. किसानों का आरोप है कि गेहूं समेत अन्य फसलों की कीमत उन्हें बाजार में मिलती ही नहीं. जबकि तालिबान कमांडर उन्हें अफीम की खेती के लिए अग्रिम राशि देते हैं. एक किलो अफीम के एवज में जहां किसानों को दो सौ से तीन सौ डॉलर मिल रहे हैं, वहीं उन्हें दस किलो गेहूं के एवज में एक डॉलर भी नहीं मिलता. ऐसे में कैसे तो रुकेगी अफीम की खेती और कैसे आतंकियों को पैसा पहुंचना बंद होगा?

के. बी. सिंग.

इंटरनेशनल मीडिया

फिर सवालों में फेसबुक

फेसबुक एक बार फिर यूजर्स की गोपनीयता के सवाल से जूझ रहा है. सामने आया है कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने में इसकी खामियों का जमकर इस्तेमाल हुआ. कंपनी ने पिछले हफ्ते कहा कि उसने ट्रंप के लिए काम करने वाली कैंब्रिज एनालिटिका और एक प्रोफेसर अलेक्जेंद्र कोगन का अकाउंट निलंबित कर दिया है, जिन पर पांच करोड़ लोगों का डाटा उनकी मर्जी के बिना इस्तेमाल करने का आरोप है. फेसबुक का यह कदम देखने में भले बड़ा लगे, पर सवाल यह है कि ऐसा करने में उसे दो साल क्यों लग गए? प्रोफेसर कोगन ने शैक्षिक शोध की आड़ में एक क्विज एप का सहारा लेकर 2014 में ही सारा डाटा हासिल किया और कैंब्रिज एनालिटिका को सौंप दिया.

द न्यूयॉर्क टाइम्स और द ऑब्जर्वर ऑफ लंदन के अनुसार, कंपनी ने इसका इस्तेमाल मतदाताओं का प्रोफाइल बनाने में किया. चिंता की बात यह है कि फेसबुक अभी तक उन यूजर्स की पहचान नहीं कर सका है, जिनके डाटा का इस्तेमाल हुआ. फेसबुक ने कैंब्रिज एनालिटिका और कोगन की डाटा डिलीट करने वाली बात भी आंख मूंदकर मान ली, जबकि टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, डाटा अब भी कंपनी के पास मौजूद है. चुनावों के बाद फेसबुक के मुखिया मार्क जुकरबर्ग ने नतीजों पर फेक न्यूज के असर के ख्याल को ही हास्यास्पद बताया था, लेकिन लगता है कि अपनी गलती स्वीकार करने में उन्होंने बहुत वक्तलगा दिया. यह तय करना तो मुश्किल है कि फेसबुक से मिले डाटा का ट्रंप की जीत में कितना इस्तेमाल हुआ, लेकिन कैंब्रिज के विरोधाभासी बयान शक को पुख्ता करने वाले हैं. अब अमेरिका व यूरोपीय संघ के अधिकारी कैंब्रिज एनालिटिका की जांच कर ही रहे हैं, मैसाचुसेट्स के अटार्नी जनरल माउरा हेली सहित कांग्रेस के कई सदस्य भी शक के दायरे में हैं. ब्रिटेन में भी यह बहस छिड़ गई है कि कहीं 2016 के ब्रोक्जिट जनमत संग्रह में भी तो ऐसा कोई गुल नहीं खिलाया गया था? फेसबुक अब भले ही माने कि उसने इसे गंभीरता से लिया है, पर इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता.

The New York Times

द न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका.

सुविचार

किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए. सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं.

आचार्य चाणक्य.

प्रतिदिन

सही चुनाव

एक राजा को अपने दरबार के किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद के लिए योग्य और विभसनीय व्यक्ति की तलाश थी. उसने अपने आस-पास के युवकों को परखना शुरू किया. लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया. तभी एक महात्मा का पदार्पण हुआ, जो इसी तरह यदा-कदा अतिथि बनकर सम्मानित हुआ करते थे. युवा राजा ने वयोवद्ध संन्यासी के सम्मुख अपने मन की बात प्रकट की. मैं तय नहीं कर पा रहा हूं. अनेक लोगों पर मैंने विचार किया. अब मेरी दृष्टि में दो हैं, इन्हीं दोनों में से एक को रखना चाहता हूं. कौन हैं ये दोनों?

संन्यासी के पूछने पर राजा ने बताया कि एक तो राज परिवार से ही संबंधित हैं, पर दूसरा बाहर का है. उसका पिता पहले हमारा सेवक हुआ करता था, उसका देहांत हो गया है. उसका यह बेटा पढ़ा-लिखा सुयोग्य है. और राज परिवार से संबंधित युवक. उसकी योग्यता मामूली है. आपका मन किसके पक्ष में हैं? मेरे मन में द्वंद्व है, स्वामी, किस बात को लेकर राज परिवार का रिश्तेदार कम योग्य होने पर भी अपना हैं, और... इस पर संन्यासी ने कहा- राजन रोग शरीर में उपजता है तो वह भी अपना ही होता है, पर उसका उपचार जंगलों और पहाड़ों पर उगने वाली जड़ी-बूटियों से किया जाता है. ये चीजें अपनी नहीं होकर भी हितकर होती हैं. राजा की आँखों के आगे से धुंध छँट गई. उसने निरपेक्ष होकर सही आदमी को चुन लिया.

नेटीजन

कविता पढ़ना उनसे सीखा

पढ़ने की शैली से कविता के अर्थ परत दर परत कैसे खोले जाएं, केदारजी इसमें माहिर थे.

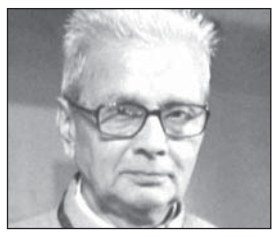

अक्सर लोग कहते थे कि केदारजी शोध में सख्ती नहीं करते, इसलिए उनके साथ एमफिल/ पीएचडी करने वालों की लंबी लाइन रहती है. मेरा अनुभव उलट था. उन्होंने मुझसे आधा दर्जन बार पीएचडी सिनॉप्सिस लिखवाई, फिर उसे पास किया. आज जब 24 साल बाद उस थीसिस को देखता हूं, तो लगता है कि उसमें से वह झांकते हुए कह रहे हैंः अगर तुमसे उस टॉपिक (शिवपूजन सहाय की साहित्यिक पत्रकारिता) पर काम नहीं करवाया होता, तो मेरी श्रद्धांजलि तुम इस तरह लिख पाते!

सर, असल बात यह है कि अगर आपने मुझसे इस टॉपिक पर काम न करवाया होता, तो मैं चाहे और जो बन जाता, पत्रकारिता और जनसंचार का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तो नहीं ही बन पाता. पाश्चात्य साहित्य, खासकर अमेरिकी कविता पर उनकी गहरी पकड़ थी. वाल्ट व्हिटमैन उनके प्रिय कवियों में थे. कविता के अर्थ को सिर्फ उसे पढ़ने की शैली से परत दर परत कैसे खोला जाता है, इसमें उन्हें महारत हासिल थी. उनसे निराला की तीन कविताएं पढ़ने का सौभाग्य मिला था वह तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति और राम की शक्तिपूजा. लगता था, मानो निराला की संवेदनशीलता केदारजी द्वारा कवितापाठ से मूर्तिमान हो रही हो. इसके बाद हमें कविता पढ़ना आ गया.

चंद्रकांत प्रसाद सिंह की फेसबुक वॉल से.

मुद्दा...

इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब

अब नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव आ गया है. पहले आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया और उसके बाद कल तक राजग का हिस्सा रही तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी.

अगर देखा जाए तो वाईएसआर कांग्रेस और तेदेपा का अविश्वास प्रस्ताव आंध्र प्रदेश की आंतरिक राजनीति की प्रतिस्पर्धा की पैदाइश है. वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी के बारे में कहा जाता था कि वह भाजपा के संपर्क में हैं. राजग से नाता तोड़ते समय तेदेपा ने यही कहा कि भाजपा जगनमोहन रेड्डी और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण के माध्यम से उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही थी. अगर वाईएसआर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रही है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि भाजपा से उसके तार जुड़े हुए थे. अगर ऐसा होता, तो वह तेदेपा के जाने के बाद राजग में आने की कोशिश करती.

सच यह है कि जगनमोहन ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू की नाक में दम कर दिया था. उन पर वाईएसआर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि नायडू मोदी सरकार में भागीदार होते हुए भी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पा रहे हैं. वह सत्ता के लिए आंध्र के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं. हालांकि अभी चुनाव में एक वर्ष से ज्यादा की देरी है, पर दोनों पार्टियों की गलत राजनीति से यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि इस मामले में दोनों एक-दूसरे को पीछे छोड़ना चाहती हैं. इस प्रतिस्पर्धी राजनीति का परिणाम जो हो, पर तत्काल यह प्रश्न तो उठेगा कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव का औचित्य क्या है? क्या आंध्र प्रदेश के हक के लिए यही एकमात्र रास्ता बचा था? क्या इसका परिणाम आंध्र प्रदेश के लिए लाभकारी रहने वाला होगा? लोकसभा का जो अंकगणित है, उसमें फिलहाल भाजपा के लिए अविश्वास प्रस्ताव कतई चिंता का कारण नहीं है. उसके पास अकेले 273 सांसद हैं. इसलिए मतदान में उसे बहुमत मिल जाएगा. वैसे भी शिवसेना को छोड़कर भी राजग के 21 वोट हैं.

सच यह है कि कोई पार्टी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती. यह अब संभव ही नहीं. जिन 11 राज्यों को पहले से विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उसके बाद किसी अन्य को मिलना 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद असंभव है. वैसे भी कई राज्य इसकी मांग कर रहे हैं. आंध्र कोई ऐसा गरीब राज्य भी नहीं है कि उसके विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ कोई सहानुभूति पैदा हो. हां, राजधानी के विकास से लेकर राजस्व में कमी आदि की भरपाई होनी चाहिए. केंद्र की ओर से वित्त मंत्री ने आंकड़े देकर यह बताया कि किस तरह केंद्र ने आंध्र की वित्तीय मदद की है और विशेष दर्जे वाले राज्यों की तरह उसे सहायता देने के लिए सरकार तैयार है. हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के लिए यह चिंता का विषय अवश्य है कि आंध्र प्रदेश में उनका एक साथी तथा एक संभावित साथी विरोध में चला गया है. सरकार के लिए यह भी चिंता का कारण है कि इससे विपक्ष की आक्रामकता बढ़ेगी और संसद के संचालन तथा विधेयक पारित कराने में कठिनाइयां आएंगी.

अवधेश कुमार.

आपकी बात

यहां भी वही सब कुछ...

केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से बेघरों को सरकारी अनुदान से घर बनाकर देने का बड़ा अभियान देश और राज्यों में चल रहा है. केन्द्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और महाराष्ट्र राज्य द्वारा रमाई, बाल्मिकी, आंबेडकर आवास योजनाएं अमल में लायी जा रही हैं.

योजना का उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन योजना क्रियान्वित करने वाली यंत्रणाएं फिर वह मनपा, नपा, गृहनिर्माण मंडल हो या ग्रामपंचायत, हर जगह भ्रष्टाचार अपने चरम पर है. शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा न तो जगह पर घर का नक्शा मंजूर किया जाता है, न यह देखा जाता है कि जगह का मालिक कानूनी है या गैरकानूनी. प्लॉट तो छोड़ो, बनने वाले घर आने-जाने वाले रास्ते पर ही बना दिये जाते हैं. एक ही व्यक्ति के नाम दो-तीन घर मंजूर कर बना दिये जाते हैं.बने घर को तोड़कर भी घर बनाए जाते हैं.योजना के तहत जिसे घर मिल रहा है वह अपने स्वार्थ के कारण चुप रहता है. घर निर्माण की मंजूरी और शासकीय निधि देने वाली यंत्रणा और उसके अधिकारी, इंजीनियर, कर्मचारी अनुदान में से अपना हिस्सा निकालते रहते हैं. केन्द्र और राज्य सरकार से विनती है कि इस होते भ्रष्टाचार को रोकें और दोषियों को दंडित किया जाए.

दयालनाथ मिश्रा,अमरावती.

आवारा सुअरों का आतंक

शहर में जिस तरह सुअरों की तादाद बढ़ रही है, चिंता का विषय है. शहर के दूरस्थ इलाके अंचल विहार, प्रभु विहार, शिवशंकर नगर में सुअरों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है.इतना सब होकर भी प्रशासन इस समस्या की ओर से आंखें मूंदे बैठा है जिसके कारण समस्या और बदतर होती जा रही है. आवारा सुअरों की वजह से नागरिकों का स्वास्थ्य प्रभावित होकर महामारी फैलने की आशंका है. मनपा प्रशासन के संबंधित पार्षदों से निवेदन है कि वे आवारा सुअरों का बंदोबस्त करें.

एम.एन.भाटिया,अमरावती.

प्रतिदिन अखबार

यह पत्र मालिक, प्रकाशक, सम्पादक नानक आहूजा द्वारा देविका वेब प्रिंटर्स, राजापेठ, अमरावती से मुद्रित कर 'प्रतिदिन अखबार' कार्यालय, देविका परिसर, ब्राह्मण सभा के पीछे, दरोगा प्लॉट, राजापेठ, अमरावती 444 606 से प्रकाशित किया है. फोन-0721-2560155/56/57/58 फैक्स-0721-2677708 E-mail :- pratidinnews@gmail.com
'प्रतिदिन अखबार' में प्रकाशित होनेवाले विभिन्न लेख, पत्र, साहित्य, लेखकों, कवियों आदि के विचारों या तथ्यों पर आधारित होते हैं. इन लेखकों के विचारों अथवा तथ्यों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है. संपादक पर मात्र सम्पादकीय लेखों का ही दायित्व है. संपादक-नानक आहूजा, समाचार संपादक-प्रवीण आहूजा.